Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-12 16-30 जून, 2025 (पाक्षिक) ₹20

विकसित भारत का अमृत काल

सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के

11 साल

9 जून, 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के शानदार 11 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं अन्य वरिष्ठ भाजपा नेतागण

सोलन (हिमाचल प्रदेश) में 02 जून, 2025 को 'तिरंगा यात्रा' में भाग लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेतागण

जयपुर (राजस्थान) में 31 मई, 2025 को 'तिरंगा यात्रा' में भाग लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा एवं अन्य नेतागण

कोलकाता में 01 जून, 2025 को विशाल 'विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन' को संबोधित करने से पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का स्वागत करते पश्चिम बंगाल भाजपा के नेतागण

नांदेड़ (महाराष्ट्र) में 26 मई, 2025 को एक विशाल जनसभा को संबोधित करने से पहले लोगों का अभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

गोवा में 08 जून, 2025 को 'नाविका सागर परिक्रमा II' के सफल समापन के बाद 'आईएनएसवी तारिणी' की भारतीय नौसेना महिला अधिकारियों को सम्मानित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **मोदी सरकार के संकल्प से सिद्धि के गौरवशाली 11 वर्ष**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से सिद्धि की गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं...

12 **'विकसित भारत' का अमृत काल: सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल**

28 **लोकमाता अहिल्याबाई भारत की विरासत की एक महान संरक्षिका थीं: नरेन्द्र मोदी**
लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर...

लेख

भारत की सुरक्षा एवं मोदी सरकार / **शिवप्रकाश** 26

अन्य

नारी शक्ति को मिला नया बल 15
मध्यम वर्ग का जीवन हुआ आसान 24
लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कार्यक्रम, जयपुर (राजस्थान) 29
तमिलनाडु में पारदर्शी एवं राष्ट्रवादी सरकार की जरूरत है : अमित शाह 30
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज 'चिनाब ब्रिज' भारत की महत्वाकांक्षा का प्रमाण है: नरेन्द्र मोदी 31
एकात्म मानववाद पर दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 32

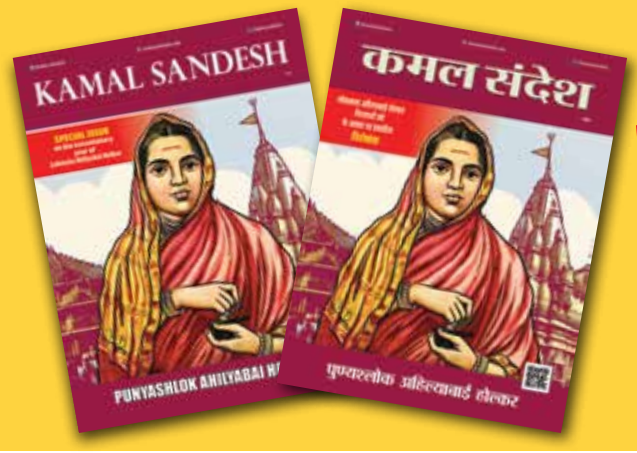

कमल संदेश विशेषांक
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई-बहनों के साथ ही जन-जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जनऔषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवाभाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया है। (09 जून, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

11 साल पहले तुष्टीकरण के साथ-साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेफ करना राजनीति की संस्कृति का तरीका बन गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार बनी है जो कि जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है।

(09 जून, 2025)

अमित शाह

मोदी सरकार के ऐतिहासिक 11 वर्ष जनसेवा के संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। #11YearsOfSeva में देश ने आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया युग देखा है। मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि जब नेतृत्व स्पष्ट, संकल्प अडिग और नीयत लोकसेवा की होती है, तब सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान बनते हैं। (09 जून, 2025)

राजनाथ सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कृषि क्षेत्र के विकास एवं किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता जगजाहिर है। पिछले #11YearsOfKisanSamman के दौरान न केवल कृषि का बजट कई गुना बढ़ाया गया बल्कि पीएम-किसान योजना के अंतर्गत किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। बीते 11 वर्षों में पीएम मोदी के अथक प्रयासों से देश के अन्नदाताओं के जीवन में एक नई समृद्धि का संचार हुआ है। (07 जून, 2025)

बी.एल. संतोष

देश पटरी पर लौट आया है, हमारी पीढ़ी आत्मविश्वास से भरी है, सभ्यता का कायाकल्प हो रहा है, युवा शक्ति प्रभावी है, महिला सशक्तीकरण अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था बेहतर है, राष्ट्र और उसके लोग अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। धन्यवाद, श्री नरेन्द्र मोदी जी

(9 जून, 2025)

निर्मला सीतारमण

पिछले 11 वर्षों में भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उल्लेखनीय यात्रा देखी है। आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने से लेकर कारोबारी विश्वास को बढ़ावा देने तक, यह वास्तविक और visible change का दशक रहा है। #11YearsOfSeva

(9 जून, 2025)

भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस (09 जून) पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश परिवार की ओर से सुधी पाठकों को **जगन्नाथ रथयात्रा** (27 जून) की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

पिछले 11 वर्षों में हुआ चमत्कारी परिवर्तन

आज जब देश 'विकसित भारत' के स्वप्नों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, पिछले 11 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा से पूरे देश में एक नए आत्मविश्वास का निर्माण हुआ है। देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं दूरदर्शी नेतृत्व में उभरते हुए भारत की चमत्कारिक उपलब्धियों को पूरा विश्व सराह रहा है। आज देश एक मजबूत, निर्णायक एवं दृढ़प्रतिज्ञ नेतृत्व में हर चुनौती को सहजता से अवसर में परिवर्तित कर रहा है। चाहे आतंकी हमला हो या सीमा पार से सैन्य आक्रमण, कोविड-19 वैश्विक महामारी हो या गरीबी के विरुद्ध युद्ध हो, देश ने हर चुनौती के ऊपर विजय प्राप्त की है। 'फ्रेजाइल फाइव' से 'टॉप फाइव' अर्थव्यवस्था की यात्रा, वह भी विश्व में सबसे अधिक विकास दर के साथ एक ऐसी उपलब्धि है जिससे हर भारतीय गौरव का अनुभव कर रहा है। पिछले ग्यारह वर्ष जनसेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के प्रति समर्पण के वर्ष रहे हैं। परिणाम एक ऐसे भारत के उद्भव के रूप में देखा जा सकता है जो बड़े स्वप्न देखता है, दूरदर्शिता से ओत-प्रोत है और अपने लक्ष्यों को उच्च कौशल के साथ दृढ़-संकल्पित होकर प्राप्त करता है।

यदि पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों को 2014 के पूर्व की परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाए, तो ये और भी अधिक अद्भुत एवं अकल्पनीय दिखते हैं। कांग्रेसनीत-यूपीए सरकार के एक दशक के कुशासन ने देश के उज्ज्वल एवं विकसित भारत का सपना छीन लिया था। इस काल में व्यापक भ्रष्टाचार, जनता के धन की खुली लूट तथा 'पॉलिसी पैरालिसिस' से पंगु शासन व्यवस्था ने भारत की आत्मा पर आघात किए थे। पूरी दुनिया को यह लगने लगा था कि भारत की कहानी अब खत्म होने के कगार पर है तथा देश विश्व के सबसे संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था 'फ्रेजाइल फाइव' की श्रेणी में चला गया था। कांग्रेस की घुटना-टेक नीतियों के फलस्वरूप इसके नेतृत्व ने देश की सुरक्षा से शर्मनाक समझौते किए तथा आतंकवादियों, अलगाववादियों एवं उनके समर्थकों को कई प्रकार की छूट देकर तुष्ट करने का प्रयास किया। देश की संप्रभुता, स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता पर हुए हर हमले से कांग्रेस का दीन-हीन एवं कमजोर नेतृत्व और भी अधिक बेनकाब हुआ। तुष्टीकरण एवं वोट-बैंक की राजनीति में फंसी हुई कांग्रेस देश के हितों से खिलवाड़ करती रही। यदि कांग्रेस नेतृत्व की पूरी कुंडली का हिसाब लगाया जाए, तो यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसने देश को जिस दिशा में धकेला, उससे पूरे राष्ट्र के हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा देश का मनोबल टूटा।

> 'फ्रेजाइल फाइव' से 'टॉप फाइव' अर्थव्यवस्था की यात्रा, वह भी विश्व में सबसे अधिक विकास दर के साथ एक ऐसी उपलब्धि है जिससे हर भारतीय गौरव का अनुभव कर रहा है। पिछले ग्यारह वर्ष जनसेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के प्रति समर्पण के वर्ष रहे हैं

पिछले 11 वर्षों से भारत न केवल अभूतपूर्व आर्थिक विकास का साक्षात्कार कर रहा है, बल्कि पहली बार एक राष्ट्र के रूप में सभ्यतागत स्वतंत्रता, एकजुटता एवं आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र से देश 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को सुदृढ़ कर रहा है। हर क्षेत्र में देश ने चमत्कारिक उपलब्धियों का अंबार लगा दिया है, जिससे भारत की विकास यात्रा आज अन्य देशों के लिए प्रेरणा बन गई है। जब अर्थव्यवस्था आज विश्व में सबसे तेज विकास दर के साथ सशक्त हो रही है, भारत वैश्विक संकट के मध्य एक चमकता हुआ सितारा प्रतीत हो रहा है। इस तेज आर्थिक विकास के कारण 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। बड़ी संख्या में अभिनव योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से किसान, मजदूर, वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, अनु.जा., अनु.जनजा., पिछड़ा वर्ग, महिला एवं युवा आज भारत के विकास दूत बन गए हैं। अब तक उपेक्षित रक्षा, हरित ऊर्जा, अवसंरचना, शिक्षा एवं कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र आज विकास एवं प्रगति के पहिए बने हुए हैं। जिसे पहले कमजोरी समझा जाता था आज वह उचित दिशा, मानसिकता एवं जनसेवा के प्रति अटूट निष्ठा के कारण देश की शक्ति बन चुकी है।

पिछले 11 वर्षों में भारत मानो एक लंबी निद्रा से जागा है तथा विश्व के राष्ट्रों के मध्य अपना समुचित स्थान प्राप्त करने के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्पित एवं करिश्माई नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की है तथा आज विश्व का 'ग्रोथ इंजन' बन गया है। आज देश 'विकसित भारत' के स्वप्नों के साथ आगे बढ़ रहा है तथा अमृतकाल के 'पंच प्रण' एवं 'ग्यारह संकल्प' इसको दिशा दिखा रहे हैं। जहां 'विकसित भारत' का स्वप्न विश्व मानवता की सेवा से प्रेरित है, वहीं भारत का उदय विश्व शांति, भाईचारा एवं स्थिरता की गारंटी है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

मोदी सरकार के 'संकल्प से सिद्धि' के गौरवशाली 11 वर्ष

मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऐसे कार्य किए हैं, जो स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं : जगत प्रकाश नड्डा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'संकल्प से सिद्धि' की गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 जून, 2025 को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में प्रेस-वार्ता को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार से ग्रस्त सरकार थी, लेकिन पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऐसे कार्य किए हैं, जिन्हें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा सुदृढ़ होने के साथ ही 'विकसित भारत' की संकल्पना सशक्त कदम से सिद्धि की ओर तेजी बढ़ रहा है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह एवं श्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख श्री अनिल बलूनी और राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख डॉ. संजय मयूख उपस्थित रहे।

राजनीतिक संस्कृति में बदलाव

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपानीत एनडीए सरकार ने 11 साल पूरे की है। 10-11 साल की अवधि को एक मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के समक्ष रख पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। 'विकसित भारत' के अमृतकाल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों से सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए जो काम किया गया है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। क्योंकि जो कार्य किए गए हैं वह अकल्पनीय और अद्वितीय हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलकर नया रूप दिया है। 11 साल पहले देश तुष्टीकरण की राजनीति में डूबा हुआ था। कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए तुष्टीकरण के साथ समाज को विभाजित करना ही राजनीतिक संस्कृति का प्रमुख हिस्सा बन गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आया है, अब पॉलिटिक्स ऑफ परफ़ोर्मेंस, जवाबदेह और जिम्मेदार सरकार वाली राजनीतिक संस्कृति आई। रिपोर्ट कार्ड की राजनीति संस्कृति शुरू हुई, यानी ऐसी सरकार जो अपने कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करती है।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत की राजनीतिक संस्कृति को बदलकर एक न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर स्थापित किया है। भाजपा की यह सरकार एक प्रभावशाली, असरदार सरकार है। यह सरकार मजबूत और निर्णायक है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन स्थापित किया गया और साहसिक निर्णय लिए गए, वे सभी जनता को साथ लेकर लिए गए। इन सभी विशेषताओं को समझना आवश्यक है।

केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार एक जिम्मेदार, जन-उत्तरदायी और जनता समर्थित सरकार है, अर्थात् जनता को साथ लेकर चलने वाली सरकार। जनभागीदारी को भी हमने बखूबी देखा है। हम सभी जानते हैं कि यह सरकार पिछले 11 वर्षों में पारदर्शिता की एक नई मिसाल बन चुकी है। यह एक पारदर्शी और भविष्य-दृष्टि वाली, यानी भविष्यवादी सरकार है।

मोदी हैं तो मुमकिन है

श्री नड्डा ने कहा कि यह सरकार भविष्य को ध्यान में रखकर देश को आगे की दिशा में ले जाने की सोच के साथ कार्य कर रही है। इसलिए आज हम विकसित भारत की बात करते हैं। इस अमृतकाल और बीते 10-11 वर्षों ने 'विकसित भारत' की नींव रखी है। इस नींव को मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यक निर्णय थे, वे सभी लिए गए हैं। आज के समय में 2014 से पहले की ओर लौटने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि 2014 से पूर्व की सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों में डूबी हुई थी। उस समय नकारात्मकता का माहौल था, जिसमें 'कुछ नहीं बदलने वाला' की सोच व्याप्त थी। लेकिन 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आशावाद ने जगह बनाई। आज भारत का आम नागरिक कहता है, "मोदी हैं तो मुमकिन है।" प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति यह धारणा बन चुकी है कि वे समस्याओं का समाधान करेंगे। यह आम नागरिक की सोच बन गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आशावाद के साथ विकास, आविष्कार और नवाचार ये तीनों बातें जुड़ चुकी हैं। आज हम विकास कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्यपद्धतियां अपना रहे हैं और नवाचार भी कर रहे हैं, इस प्रकार विकास के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में, "विकसित भारत का आधार यही दशक बनेगा।" इसी कार्य के अंतर्गत उनके नेतृत्व में दी गई नीतियां- प्रदर्शन, परिवर्तन और सुधार, ये तीन बातें हर नीति में स्पष्ट दिखाई देती हैं। हर नीति में कुछ नया नजर आता है। पुरानी नीतियों में जो बदलाव हुए हैं, वे सुधार की आवश्यकता और परिवर्तन की मांग के कारण किए गए हैं और उनके लिए ठोस कार्य भी किए गए हैं। यह मूलभूत सिद्धांत पिछले 11 वर्षों में अपनाया गया है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच पर आधारित है— "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।" अनेक चुनौतियां आईं, लेकिन इसके बावजूद हमारा मुख्य सिद्धांत हमेशा स्पष्ट और मजबूत रहा है।

साहसिक निर्णय लिए गए

श्री नड्डा ने कहा कि अगर साहसिक निर्णयों की बात करें, तो 11 वर्षों में लिए गए सभी निर्णायक कदमों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना बेहद कठिन है। फिर भी कुछ फैसले ऐसे हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ लाए हैं। अनुच्छेद 370 का हटाया जाना एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव था, जिसे देश मान चुका

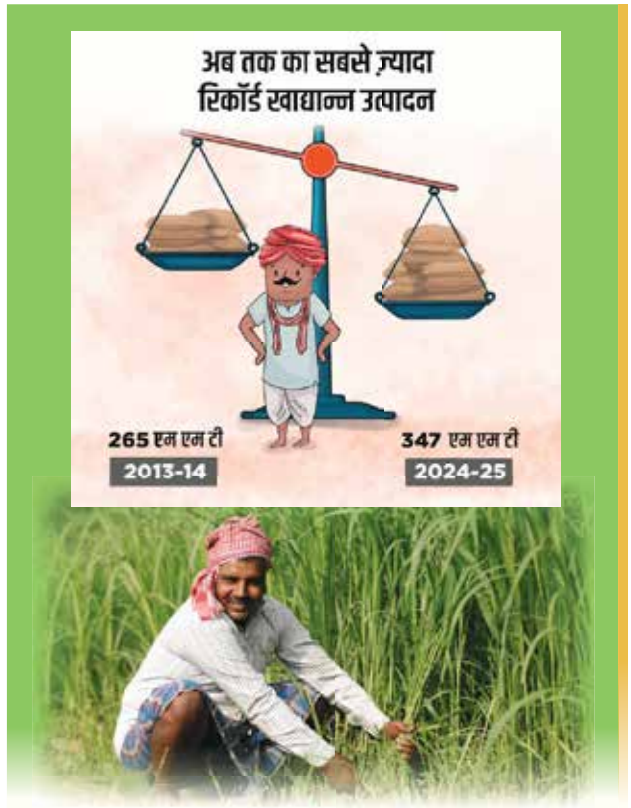

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष

मोटे अनाज के महत्व को पहचान कर लोगों को पोषक भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराने और स्वदेशी व वैश्विक मांग का सृजन करने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को **अंतरराष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष** के रूप में घोषित कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत के इस प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और मार्च 2021 में ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष के रूप में घोषित कर दिया।

था कि यह संभव नहीं है। "यह नहीं हो सकता" की धारणा आम हो चुकी थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह धारणा टूट गई, अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ और आज हम इसके परिणाम देख रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव में 58.46 प्रतिशत और विधानसभा चुनाव में 63 प्रतिशत तक टर्नआउट पहुंचना स्पष्ट करता है कि ये परिवर्तन एक साहसी निर्णय का असर है। इसी तरह तीन तलाक की प्रथा, जो मानवता के लिए एक त्रासदी थी, पर वर्षों तक चुप्पी छाई रही। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही, लेकिन कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। मोदी सरकार ने तीन तलाक को समाप्त कर यह साबित किया कि वह महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में तीन तलाक जैसी व्यवस्था पहले ही खत्म हो चुकी थी, जबकि भारत में यह जारी था। इसे खत्म कर भारत ने मानवता की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया। वक्फ अधिनियम में सुधार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। देश हित और समुदाय हित के लिए नया वक्फ अधिनियम लाया गया, जो देश की समरसता और पारदर्शिता की दिशा में एक ठोस प्रयास था। नागरिकता संशोधन अधिनियम, नोटबंदी, महिला आरक्षण, ये सभी ऐसे निर्णय हैं जिन पर वर्षों से चर्चा होती रही, लेकिन निर्णायक कदम नहीं उठाए गए। तीन दशकों से लंबित महिला आरक्षण को 33 प्रतिशत तक सुनिश्चित करना मोदी सरकार के साहसिक और निर्णायक नेतृत्व का उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक अनुशासन लाने के लिए मोदी सरकार ने योजनाबद्ध ढंग से फैसले लिए। बजट की प्रस्तुति को एडवांस किया गया, योजना और गैर-योजना व्यय के बीच के भेद को समाप्त किया गया और रेल बजट को मुख्य बजट में समाहित कर समेकित आर्थिक दृष्टिकोण अपनाया गया। इस आर्थिक दूरदर्शिता का परिणाम यह है कि आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह लगातार चौथा वर्ष है जब भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा है। प्रति व्यक्ति आय में 67 प्रतिशत, विदेशी मुद्रा भंडार में 135 प्रतिशत, निर्यात में 825 अरब अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड स्तर, एफडीआई में 106 प्रतिशत, टैक्सपेयर्स की संख्या में 127 प्रतिशत और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 238 प्रतिशत की वृद्धि यह दर्शाती है कि सरकार ने न केवल फैसले लिए, बल्कि उन फैसलों को ज़मीन पर उतारकर परिवर्तन भी लाया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को 'ब्राइट स्पॉट' कहता है, वर्ल्ड बैंक भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था कहता है और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम यह तक कह चुका है कि भारत 2025 और 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन बनने जा रहा है। यह तब संभव हुआ है जब वैश्विक परिस्थितियां विपरीत थीं। भारत की अर्थव्यवस्था ने न केवल खुद को स्थिर बनाए रखा, बल्कि हर चुनौती का डटकर सामना किया।

उत्तरदायी सरकार

श्री मोदी ने कहा कि जब हम एक उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि यह सरकार केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं रही, बल्कि हर परिस्थिति में सक्रिय रूप से कार्यरत रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से न केवल भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया, बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी भारत के झंडे तले सुरक्षित निकासी मिली। कोविड काल में वंदे भारत मिशन के माध्यम से 67 लाख से अधिक लोगों को स्वदेश लाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। यमन में चलाए गए ऑपरेशन राहत के अंतर्गत न सिर्फ 5 हजार भारतीय नागरिकों, बल्कि 1 हजार से अधिक अन्य देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर लाया गया। नेपाल में आए भूकंप के दौरान भारत की राहत टीम सबसे पहले काठमांडू पहुंची और राहत कार्य प्रारंभ किया। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने 150 से अधिक देशों को वैक्सीन प्रदान की, जिनमें से कम से कम 48 देशों को यह निःशुल्क दी कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, वैसा उदाहरण दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिला। यह इस शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी थी, जिसमें भारत ने वैज्ञानिक, प्रशासनिक और मानवीय दृष्टि से अद्वितीय नेतृत्व का परिचय दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह लड़ाई सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रही, बल्कि जन-जन की लड़ाई बन गई। यही एक जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार की पहचान है, जो निर्णय लेती है, उन्हें ज़मीन पर उतारती है और परिणाम लाकर दिखाती है।

उन्होंने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड की लड़ाई जनता के साथ मिलकर लड़ी। उन्होंने यह तय किया कि इस संघर्ष में जनता को साथ लेकर चलना है और इसी सोच से जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव विचार सामने आया। जहां अन्य देशों में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और वैक्सीनेशन का विरोध देखा गया, वहीं भारत अकेला ऐसा देश रहा जिसने 220 करोड़ से अधिक डोज़, वह भी डबल डोज़, पूरी तरह निःशुल्क लगाकर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया। यही एक उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार की पहचान है और कोविड के संदर्भ में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, चाहे वे अनुसूचित जाति के भाई-बहन हों, अन्य पिछड़ा वर्ग हो या हमारे आदिवासी समुदाय के लोग। इनके लिए विशेष नीतियां, योजनाएं और छात्रवृत्तियां प्रारंभ की

गईं, जो पूरी तरह एससी, एसटी और ओबीसी समाज को समर्पित हैं। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान देते हुए 'वीमेन लेड गवर्नमेंट' की भावना को केंद्र में रखा गया और महिलाओं को आगे लाने के लिए ठोस प्रयास किए गए। स्वास्थ्य क्षेत्र में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक और उसके बाद टीकाकरण तक सभी चरणों में भारत सरकार की योजनाएं सक्रिय रही हैं। मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, वह भी वेतन सहित, एक बड़ा और संवेदनशील कदम रहा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को सशक्त किया गया। जब चंद्रयान की तस्वीरें सामने आईं, तो उसमें सबसे अधिक महिला वैज्ञानिक दिखाई दीं। आज महिलाएं पायलट से लेकर सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त कर रही हैं। एनडीए में भी अब लड़कियों की भर्ती हो रही है और वे पास आउट भी हो रही हैं। देश के 73 सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों को प्रवेश मिल रहा है। 'लखपति दीदी' योजना और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। समाज के वे वर्ग, जिन्हें पहले केवल नजरअंदाज़ किया जाता था, आज उन्हें केंद्र में लाकर भरोसा दिया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं, इन सभी की मुख्यधारा में भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

गरीब कल्याण

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब कल्याण को केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक क्रियान्वयन का विषय बनाया है। 'गरीबी हटाओ' जैसे पुराने नारों से आगे बढ़कर इस सरकार ने गरीबों के कल्याण को साकार रूप दिया है। आंकड़े स्वयं इस बदलाव के साक्षी है, 25 करोड़ लोग अब तक गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। यह केवल हमारा दावा नहीं है, बल्कि नीति आयोग और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं। भारत में अत्यधिक गरीबी में 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ और मकानों के निर्माण का संकल्प लिया गया है, जिसे स्वीकृति मिल चुकी है। यदि आज आप गांवों की यात्रा करें, तो पहले जहां खपरैल और फूस के घर दिखाई देते थे, वहां अब पक्के मकान खड़े हैं। सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में पहले जो सड़कें अधूरी और टूटी-फूटी रहती थीं, वे अब हाईवे में बदल चुकी हैं। इनकी गति और गुणवत्ता इतनी उन्नत हो चुकी है कि डायवर्जन लेने के लिए अब दो किलोमीटर पहले से ही सतर्क रहना पड़ता है। यह आज के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का परिचायक है। उज्ज्वला योजना, 100% विद्युतीकरण और जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 364% की वृद्धि के साथ घरों में नल से जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इन सभी योजनाओं और उनके प्रभावी निष्पादन से यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार न केवल जवाबदेह और संवेदनशील है, बल्कि परिणाम देने वाली एक सक्रिय सरकार भी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को देश की मुख्यधारा में लाया गया है। इसी तरह,

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने भी उन्हें आर्थिक सुरक्षा के दायरे में लाकर सशक्त किया है। 100% विद्युतीकरण की दिशा में सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और उजाला योजना के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बीमा योजनाओं की बात करें तो जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा के अंतर्गत लगभग 40 करोड़ लोगों को कवर किया गया है। ये वे समाज के हाशिए पर खड़े लोग हैं जो पहले बीमा जैसी सुविधा लेने की स्थिति में नहीं थे। जनभागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोविड काल है, जब भारत में सरकार के साथ जनता ने भी समान रूप से मिलकर महामारी से लड़ाई लड़ी। कुछ राजनीतिक दलों ने डीमोनिटाइजेशन पर जनता को भड़काने की कोशिश की, तब भी देश का आम नागरिक शांतिपूर्वक घंटों बैंक की कतार में खड़ा रहा और डीमोनिटाइजेशन के निर्णय का समर्थन किया। यह इस बात का प्रमाण है कि जब नेतृत्व पर भरोसा होता है, तो जनता सक्रिय सहभागिता निभाती है। पहले शिक्षा नीति जैसे मुद्दों पर शिक्षा मंत्रियों की साझा बैठक तक नहीं हो पाती थी, लेकिन आज नई शिक्षा नीति 2020 व्यापक परामर्श और सर्वसम्मति से बनाई गई है। यही स्थिति 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के साथ भी रही, वह भी बिना किसी विवाद के पारित हुई, क्योंकि इसमें भी समग्र दृष्टिकोण और संवाद की व्यापकता रही। स्वच्छ भारत मिशन केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने स्वास्थ्य संकेतकों में भी सुधार लाया है।

पारदर्शी सरकार

श्री नड्डा ने पारदर्शी सरकार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया कि आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लेनदेन की संख्या में 130 गुना वृद्धि हुई है। JAM ट्रिनिटी (जनधन, आधार, मोबाइल) के जरिए लगभग 3.9 लाख करोड़ रुपये की लीकेज रोकी गई है। 'प्रगति' मंच के माध्यम से सभी योजनाओं और रुके हुए प्रोजेक्ट्स की निगरानी की जाती है, जिससे जनता को योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है। कोओपेरेटिव फेड्रलिज्म केवल नारा नहीं, बल्कि जीएसटी इसका प्रमुख उदाहरण है। जीएसटी लागू होने से पहले 17 कर और 13 उपकर थे, जिन्हें एक साथ समाहित किया गया और सभी राज्य एक साथ आए। अब टैक्स संग्रहण 20.8 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक पहुंच गया है। राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन में 283% की वृद्धि दी गई है, जबकि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से राज्यों की अनदेखी का दावा करते हैं जबकि आंकड़े बताते हैं कि राज्यों के केंद्रीय शेयर में भारी इजाफा हुआ है। कोविड के दौरान 11 औपचारिक बैठकें आयोजित की गईं, जो को-ओपेरेटिव फेड्रलिज्म का उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बार-बार कहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों को आगे बढ़ाना होगा। इसी संदर्भ में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की अवधारणा भी प्रस्तुत हुई, जिससे पिछड़े जिलों को मुख्यधारा में लाकर सशक्त बनाया जा रहा है। आज भारत एआई मिशन, योजनाओं का विस्तार, चंद्रयान-3, आदित्य एल-1 और गगनयान मिशन जैसे भविष्य की योजनाओं पर कार्य कर रहा है। ये सभी योजनाएं यह दर्शाती हैं कि देश को भविष्य की दृष्टि से किस तरह देखा जा रहा है और ये फ्यूचरिस्टिक सरकार के श्रेष्ठ उदाहरण हैं।

'विकसित भारत' का संकल्प

श्री नड्डा ने कहा कि 'विकसित भारत' की कल्पना को साकार करना हमारी प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर चुनौती का सामना सीधा किया है, कभी इधर-उधर की बात नहीं की। उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह स्पष्ट वक्तव्य था, "इसका जवाब दिया जाएगा।" देश के इतिहास में पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने इतने स्पष्ट शब्दों में आतंकियों को सीधी चेतावनी दी और जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पुलवामा हमले के समय भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा," और फिर बालाकोट एयरस्ट्राइक हुई। पहलगाम हमले के बाद बिहार की एक जनसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा, "अब तुम्हें जवाब कल्पना से भी परे मिलेगा।" यह स्पष्ट करता है कि भारत की रणनीति में अब निर्णायकता और आक्रामकता एक 'न्यू नॉर्मल' बन गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी कहा है कि अब किसी भी आतंकवादी घटना को ऐक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और 'न्यूक्लियर युद्ध' की गीदड़भभकी को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादी और उन्हें संरक्षण देने वालों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। यह सरकार बीते 11 वर्षों में हर चुनौती चाहे वह आतंकी हमला हो या किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा चुनौती का सीधा और निर्णायक जवाब देने में सक्षम रही है। यही एक सशक्त, आत्मविश्वासी और जवाबदेह राष्ट्र की पहचान है।

नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई

श्री नड्डा ने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म (वामपंथी उग्रवाद) और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे स्वयं छह वर्षों तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे और कोंटा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा जैसे नक्सल-प्रभावित जिलों का दौरा कर चुके हैं। पहले देश में 126 जिले नक्सल प्रभावित माने जाते थे, जो अब घटकर मात्र 18 रह गए हैं। हिंसा में 53% की कमी आई है, सुरक्षा बलों की हताहत संख्या में 72% की गिरावट दर्ज की गई है और कुल मृत्यु दर में 70% तक की कमी हुई है। इससे स्पष्ट है कि भारत अब नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में

तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले की सरकारों की सोच ऐसी थी कि सीमा पर सड़कें नहीं बननी चाहिए ताकि दुश्मन उसका लाभ न उठा सकें। लेकिन, आज़ादी के 75 वर्षों में यह सोच बदली और अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सीमाओं को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अब तक लगभग 8 हजार किलोमीटर सीमा सड़कें और 400 से अधिक स्थायी पुल बनाए जा चुके हैं। आज अटल टनल, सेला टनल और श्रीकुंला टनल जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्माण किए जा रहे यह सब इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार केवल शब्दों की नहीं, बल्कि कर्मों की राजनीति करती है, जो देश की सुरक्षा, विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक है।

समस्याओं को टालने के बजाय उनका समाधान

श्री नड्डा ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सड़कें, हवाई मार्ग, रेलवे और पुलों पर लंबी चर्चा हो सकती है लेकिन चुनावी संदर्भ में विशेष रूप से यह कहना जरूरी है कि नरसिंह राव जी के समय 1995 में चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट का शिलान्यास रखा गया था, जिसे बाद में श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 जून को, यानी अभी तीन दिन पहले, इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। यह तथ्य हमें यह समझाता है कि मोदी सरकार ने समस्याओं को टालने के बजाय उनका समाधान किया है। सरकार ने समाज के हर वर्ग की चिंता की और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किया। पिछले 11 वर्षों में वह विकास हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकसित भारत की दिशा में लंबी छलांग ली है, जिसमें सभी समाज वर्गों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया। 11 साल के कार्यकाल में हुए इन महत्वपूर्ण कार्यों, नीतियों और कार्यक्रमों को समझाना आसान नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने देश को नए मुकाम पर पहुंचाया है।

मुख्य बिंदु

- श्री नरेन्द्र मोदी सरकार जन-आधारित और पारदर्शी शासन की प्रतीक है, जिसने बीते 11 वर्षों में भविष्यदृष्टि से आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। यही कारण है कि 'विकसित भारत' और 'अमृतकाल' को हम जमीन पुर उतरते हुए देख रहे हैं।
- श्री नरेन्द्र मोदी सरकार रेस्पोंसिव, रेस्पोंसिबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, करप्शन-फ्री गवर्नमेंट है। यह रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांस्फॉर्म की अवधारणा को चरितार्थ करने वाली गवर्नमेंट है।
- 11 वर्ष पहले देश तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति में डूबा था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जवाबदेही और रिपोर्ट कार्ड वाली राजनीतिक संस्कृति स्थापित हुई है जो अब न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर बन चुका है।
- आज भारत का आम नागरिक कहता है, "मोदी हैं तो मुमकिन है।"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति यह धारणा बन चुकी है कि वे समस्याओं का समाधान करेंगे। यह आम नागरिक की सोच बन गई है।
- राष्ट्रहित में मोदी सरकार ने हमेशा ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, अनुच्छेद 370 को हटाना, तीन तलाक को खत्म करना, नया वक्फ कानून और सीएए लागू करना तथा विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण इसके उदाहरण हैं।
- आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में अब निर्णायकता और आक्रामकता एक 'न्यू नॉर्मल' बन गई है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक छवि को दुनिया भर में स्थापित किया है।
- पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने एससी-एसटी-ओबीसी समेत समाज के सभी वर्गों के सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी है। महिलाओं को नेतृत्व में लाने के लिए उन्हें सेना, शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के हर क्षेत्र में अवसर दिए गए हैं।
- पहले देश में 126 नक्सल प्रभावित जिले थे, जो अब घटकर 18 रह गए हैं। हिंसा में 53%, सुरक्षा बलों की हताहत संख्या में 72% और कुल मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। भारत नक्सलवाद के खात्मे की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।
- मोदी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प के साथ अनुच्छेद 370 को हटाकर असंभव दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया। आज वहां लोकतंत्र फल-फूल रहा है, विधानसभा चुनाव में 63% मतदान मोदी सरकार के साहसिक निर्णयों का परिणाम है।
- चाहे आतंकी हमला हो या किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा चुनौती, बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने हर चुनौती का सीधा और निर्णायक जवाब दिया है। यह एक सशक्त, आत्मविश्वासी और जवाबदेह राष्ट्र की पहचान है।
- भाजपा सिर्फ 'गरीबी हटाओ' का नारा नहीं देती, बल्कि गरीबों का कल्याण करके दिखाती है। अंतराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और अति गरीबी में 80% की भारी कमी आई है।
- स्वच्छ भारत अभियान केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुधार में भी बड़ा योगदान दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन में लगभग 130 गुना वृद्धि हुई और JAM त्रिनिटी ने 3.9 लाख करोड़ रुपये की लीकेज को रोका है।
- राज्यों के टैक्स डिवोल्यूशन में 283% की वृद्धि दी गई है, इसके बावजूद कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक कारणों से राज्यों की उपेक्षा की जा रही है, जबकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय शेयर में काफी इजाफा हुआ है। ■

विकसित भारत का अमृत काल

सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल

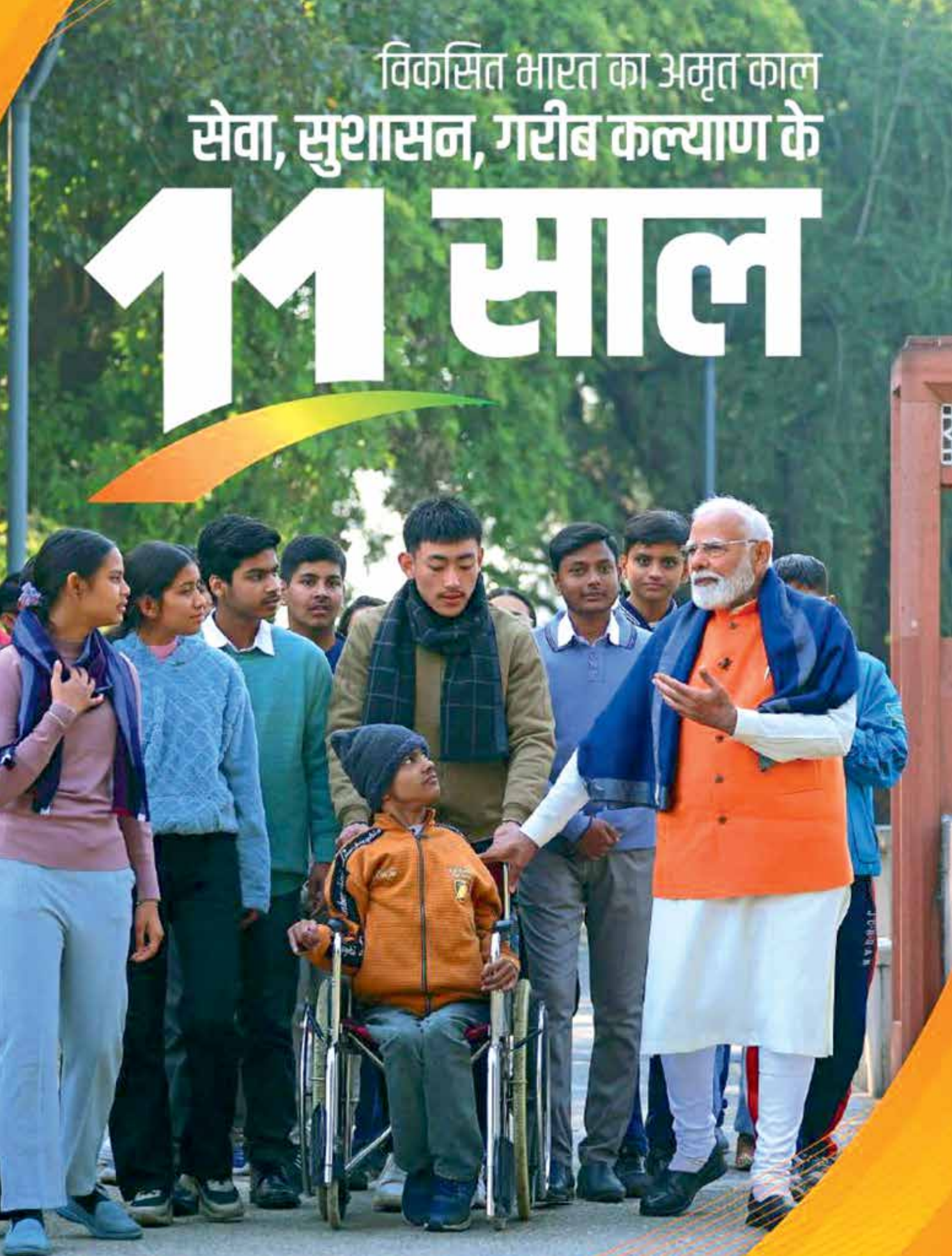

गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान

मुख्य बातें

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
के तहत
81 करोड़
लोगों को मुफ्त अनाज

15+ करोड़
घरों में नल से जल कनेक्शन

प्रधानमंत्री आवास योजना
के तहत
4 करोड़
से ज्यादा
घरों का निर्माण

स्वच्छ भारत
के तहत
12 करोड़
शौचालयों का निर्माण

पीएम स्वनिधि
के माध्यम से
68 लाख
रेहड़ी-पटरी वालों को मिला आर्थिक बल

मुद्रा योजना
के तहत
छोटे उद्यमियों को मिले
52.5 करोड़
से ज्यादा के लोन

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को
संवैधानिक दर्जा

COVID लॉकडाउन के दौरान
20 करोड़
महिलाओं के खातों में कैश ट्रांसफर

स्टैंड अप इंडिया
के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को
₹14,700+ करोड़ रुपये
से अधिक का लोन

वर्तमान में केंद्र में
60%
मंत्री एससी, एसटी या ओबीसी हैं

2014 से एकलव्य आवासीय विद्यालयों की संख्या में
चार गुना
से अधिक वृद्धि

112 आकांक्षी जिले
विकास के मापदंडों पर अपने राज्यों के औसत से ज्यादा बढ़े

सरकार के बड़े काम

आंकड़े गवाह हैं कि सरकार गरीबों के लिए बड़ा सोचती है। बीते 11 वर्षों के दौरान करोड़ों परिवारों को पहली बार सबसे जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं।

55.22 करोड़
जन-धन खाते खोले गए

51+ करोड़
लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल

23.64 करोड़
लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ

77+ करोड़
आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउंट बने

4 करोड़
से अधिक आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत

₹ 43.8 लाख करोड़
से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में 2014 से

100% इच्छुक घरों का
सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण

10.33 करोड़ से अधिक
उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन

नारी शक्ति को मिला नया बल

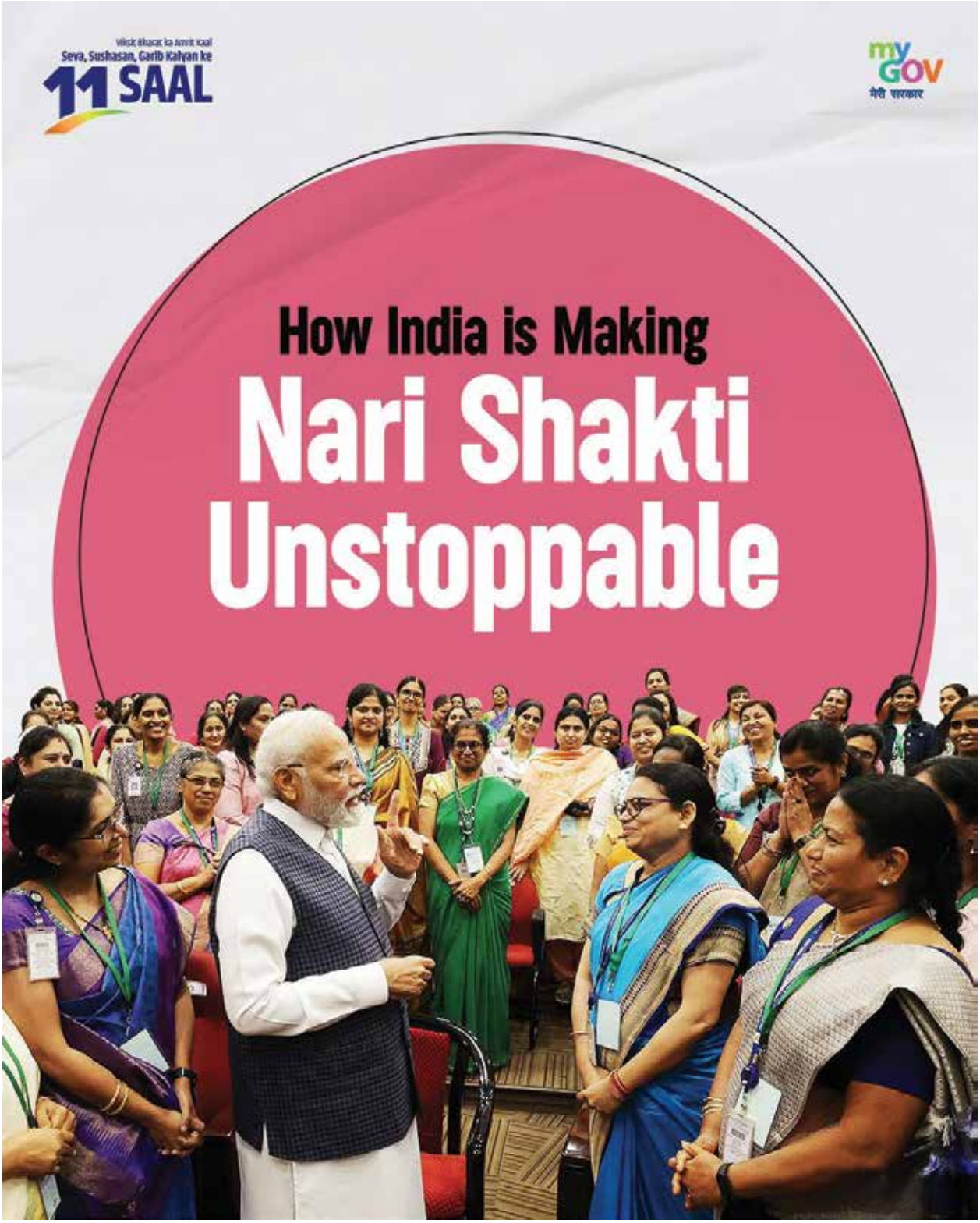

मुख्य बातें

भारत में पहली बार प्रति 1,000 पुरुषों पर
1,020 महिलाएं
(एनएफएचएस-5)

सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर
26 सप्ताह
किया गया

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत
6 करोड़
से अधिक निःशुल्क प्रसवपूर्व जांच की गई

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत
3.98 करोड़
से अधिक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को **₹18,593 करोड़** से अधिक की राशि वितरित की गई

जन औषधि केंद्रों में **₹1** की दर से
77 करोड़
से अधिक सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए गए

4.2 करोड़
सुकन्या समृद्धि खाते

10.33 करोड़
से अधिक धुआँ मुक्त रसोई

लगभग 2.75 करोड़ **पीएम आवास-ग्रामीण लाभार्थियों** में से
73%
महिलाएँ हैं

10 करोड़
महिलाओं को 90 लाख से अधिक **स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी)** में संगठित किया गया है

महिलाओं को
₹14.72 लाख करोड़
के 35.38 करोड़ (68%) मुद्रा ऋण दिए गए

2023 में
मातृ मृत्यु दर
घट कर 80 हो गई है

3 करोड़
महिलाओं को **लखपति दीदी** बनाने का संकल्प

किसानों का कल्याण सुनिश्चित

मुख्य बातें

वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2025-26 में कृषि बजट में
5 गुना
की वृद्धि

कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से
₹1 लाख करोड़

प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों को
₹3.7 लाख करोड़
वितरित किए गए

करीब
25 करोड़
मृदा स्वास्थ्य कार्ड
वितरित किए गए

वर्ष 2025-26 में **केसीसी** के तहत ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर
₹5 लाख
की गई

पीएम फसल बीमा योजना के तहत दावों में
₹1.75 लाख
से अधिक का निपटान

एमएसपी पर **दलहन** खरीद में
7350%
की वृद्धि

पीएम धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के
1.7 करोड़
किसानों को लाभ

eNAM के माध्यम से अब
1473 मंडियां
जुड़ी हुई हैं

एमएसपी पर **तिलहन** खरीद में
1500%
की बढ़ोतरी

2021-26 के लिए **पीएम कृषि सिंचाई योजना** के लिए
₹93,000+ करोड़ आवंटित

उच्च उपज वाले बीजों पर
राष्ट्रीय मिशन
के लिए
₹100 करोड़
की घोषणा

किसानों की आय के साधन बढ़े

सोलर पैनल

बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगा कर आमदनी में बढ़ोतरी को प्रोत्साहन

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि

63.56% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज करते हुए दूध उत्पादन 14.6 करोड़ टन से बढ़कर 23.9 करोड़ टन हुआ।

Blue Revolution की शुरुआत

मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग का गठन, मत्स्य उत्पादन रिकॉर्ड 184 लाख टन तक पहुंचा।

SWEET REVOLUTION

पिछले 11 वर्षों में शहद के निर्यात में तीन गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है

इथेनॉल की खरीद

इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) में अप्रैल 2025 तक इथेनॉल की खरीद में 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से 440+ करोड़ लीटर की वृद्धि हुई

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण

प्लेटफॉर्म वर्कर्स पर ध्यान

एग्रीगेटर्स जैसे नए युग के प्लेटफॉर्म के विकास का मतलब श्रमिकों के लिए नए प्रकार की नौकरियां। **भारत उन पहले कुछ देशों में से एक है जो अपने श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोचता है।**

एग्रीगेटर्स को लाभ प्रदान करने के लिए टर्नओवर के 1-2% के योगदान पर 5% तक फायदे का प्रावधान किया गया है।

e-Shram सशक्तिकरण के लिए

30.82 करोड़
असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत

400 व्यवसाय, कौशल सेट, शिक्षा, आय, सामाजिक श्रेणी, बैंक खाता विवरण संबद्ध

36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश असंगठित श्रमिकों को सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, डाटा साझा करने हेतु इ-श्रम से जुड़े

प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन

51.31 लाख
असंगठित क्षेत्र के कामगार स्वघोषणा के आधार पर पंजीकृत

₹3,000
न्यूनतम पेंशन है, जो उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी

उद्यमिता से सशक्तिकरण

PM-SVANidhi योजना के तहत 68 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लोन सुविधा

52.5+ करोड़ MUDRA लोन में से आधे से ज़्यादा SC/ST/OBC उद्यमियों को

Standup India के तहत महिलाओं/SC/ST उद्यमियों के लिए 2.74 लाख ऋण स्वीकृत

सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतीकों को पहचान

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर से जुड़े 5 मुख्य स्थलों का 'पंचतीर्थ' के रूप में पुनर्विकास

15 नवंबर, 2024 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। मई 2025 तक, भारत सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नेताओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए 10 राज्यों में 11 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को स्वीकृति दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी प्रमुखजन को श्रद्धांजलि दी और पूरे भारत में आदिवासी समुदायों के उत्थान के उद्देश्य हेतु कई पहलों की शुरुआत की।

युवा

मुद्रा योजना से युवा उद्यमियों के लिए ऋण

युवा भारत के सपनों को पंख देने और आत्मनिर्भरता के अवसर पैदा करने के लिए ₹ **33.8 लाख करोड़** से अधिक के **52.5+ करोड़** ऋण स्वीकृत

स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन

भारत तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न सिस्टम बन गया है। **1,60,000+** मान्यता प्राप्त स्टार्टअप **17.6 लाख** से अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं

खेल जगत में खुले नए द्वार

खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसी योजनाओं से प्रेरित होकर टोक्यो ओलंपिक, पैरालंपिक और हांगझोऊ एशियन गेम्स में **भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन**

अन्नदाता

पीएम किसान सम्मान निधि से खुशहाल किसान

किसानों को हर साल ₹ 6,000 की आय सुनिश्चित की गई; उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए अब तक **11+ करोड़ किसानों को ₹ 3.7 लाख करोड़ की सहायता** की सहायता दी गई

किसान क्रेडिट कार्ड से तत्काल ऋण की सुविधा

किसान क्रेडिट कार्ड के साथ **7.71 करोड़ किसानों को ₹10 लाख करोड़** प्रदान किए गए हैं, जिससे कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण तक सरल और किफायती पहुंच संभव हो गई है।

कृषि अवसंरचना कोष से कृषि बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण

एआईएफ के तहत **₹1 लाख करोड़** के निवेश को स्वीकृति दी गई, जो खेती के तरीकों को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

नारी शक्ति

सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा

10 वर्ष से कम उम्र की हर बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए **4.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खुले,** एक सशक्त भविष्य का वादा

जल जीवन मिशन से स्वच्छ पेयजल

15.6 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की सभी महिलाओं ओर परिवारों का अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित

मध्यम वर्ग का जीवन हुआ आसान

मुख्य बातें

12.75 लाख रुपये तक की आय तक

फुल टैक्स रिबेट

देश के **99.6%** जिलों में सिर्फ 22 महीनों में

5G सेवा शुरू

उमंग ऐप

के माध्यम से **2,297**

से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंच

रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को फिर से चलाने के लिए **स्वामी फंड** के तहत

₹37,000 करोड़

पूरे देश में **रेरा** द्वारा

1 लाख से अधिक

मामलों का निपटारा

यूपीआई उपयोगकर्ताओं की संख्या में अब करीब

46 करोड़

व्यक्ति और

6.5 करोड़

व्यापारी हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) के तहत

4 करोड़

से अधिक घर

मेट्रो 2014 में 5 शहरों से बढ़कर अब (2025)

23 शहरों में पहुंची

UDAN

योजना के तहत **1.50+ करोड़** लोगों ने सस्ती हवाई यात्रा का लाभ उठाया

52.14 करोड़

से अधिक **डिजिलॉकर** उपयोगकर्ता

इंटरनेट डेटा की कीमतें

97% घटी

अब सभी शहर

ओडीएफ*

घोषित

*खुले में शौच मुक्त

भारत की सुरक्षा एवं मोदी सरकार

शिवप्रकाश

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 'संकल्प से सिद्धि' अभियान चला रही है। संपूर्ण देश में मोदी सरकार की सफलता पर प्रेसवार्ताएं, प्रदर्शनी, विचार संगोष्ठी, जनसभाएं एवं ग्राम स्तर पर चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सोशल मीडिया द्वारा योजनाओं की जानकारी एवं अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हो रहा है। गरीब कल्याण, ढांचागत विकास, अन्तर्बाह्य सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक उत्थान एवं विदेशों में बढ़ता भारतीय सम्मान - सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां 11 वर्ष में प्रगति की गवाह है। भारत सहित विश्व की अनेक संस्थाओं एवं प्रमुख व्यक्तियों ने इस ऐतिहासिक सफलता की प्रशंसा की है। रक्षा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की उपलब्धियां ऐतिहासिक है।

चाणक्य नीति में कहा कि "शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते" शास्त्रों की चर्चा भी तभी संभव है जब राष्ट्र सभी प्रकार से सुरक्षित हो। सिद्धांत कितना भी श्रेष्ठ हो उसकी सफलता उस सिद्धांत का अनुसरण करने वालों की शक्ति पर ही निर्भर करती है। इसी कारण विद्वानों ने शक्ति को ही शांति का आधार बताया है। राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता "क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो" में इस सिद्धांत को ही प्रतिपादित करते हैं।

भारतीय जनसंघ ने अपने 1964 के पटना अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करते हुए मांग की थी कि भारत को परमाणु बम बनाने के सभी प्रयत्न करने चाहिए। 'सिद्धांत एवं नीतियां' नामक दस्तावेज में भी परमाणु अस्त्रों का निर्माण करने की बात की थी। प्रस्ताव प्रतिपादन करते समय कहा गया था कि हमारे आराध्य सभी देवी-देवता धर्म संस्थापना के लिये शस्त्रधारी हैं। इसलिए भारत माता भी परमाणु बमधारी होनी चाहिए। इसी नीति का अनुसरण करते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 1999 में पोखरण परमाणु विस्फोट कर विश्व में भारत के सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया था। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद देश अपने हितों की सुरक्षा करने में समर्थ बने, इस प्रकार की नीति पर चला। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी का उदाहरण है। जहां कांग्रेस सरकार में आतंकियों के लिए 'जी' जैसे सम्मानपूर्वक शब्दों का उपयोग एवं 'बिरयानी खिलाना' जैसे उपक्रम चल रहे थे, वहीं मोदी सरकार में सेना और सुरक्षा बलों को आतंक से लड़ने के लिए छूट एवं सुरक्षा बलों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाये गए।

> **चाणक्य नीति में कहा कि "शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते" शास्त्रों की चर्चा भी तभी संभव है जब राष्ट्र सभी प्रकार से सुरक्षित हो। सिद्धांत कितना भी श्रेष्ठ हो उसकी सफलता उस सिद्धांत का अनुसरण करने वालों की शक्ति पर ही निर्भर करती है**

रक्षा क्षेत्र का बजट 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपए था, अब 2025-26 के लिए वह बढ़कर 6.81 लाख करोड़ रुपए अर्थात् तीन गुना से अधिक हो गया है। 2015 कैग रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सेना के पास केवल 20 दिन का गोला बारूद उपलब्ध था। व्यक्तिगत सैनिक स्तर पर सैनिकों को अब स्वदेशी रूप से निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली बुलेटप्रूफ जैकेट, उन्नत हेलमेट, नई बैटल ड्रेस यूनिफॉर्म (NBDU), नाइट विजन डिवाइस (NVDs) और थर्मल इमेजर उपलब्ध करायी गई। मोदी सरकार के आने के बाद सेना के समन्वय के लिए लंबित मांग सीडीएस की नियुक्ति का निर्णय हुआ। 'ऑपरेशन सिन्दूर' में तीनों सेनाओं के समन्वय में हमने इस निर्णय की भूमिका को अनुभव किया है। शस्त्रों की खरीद के लंबे समय से लंबित निर्णयों का भी शीघ्र निस्तारण होते हुए हम देख चुके हैं। फ्रांस से आने वाले राफेल की खरीद इसी प्रक्रिया का परिणाम है। एस-400, सुखोई-30, इजराइल से ड्रोन, हैमर मिसाइल, चिनूक हेलिकॉप्टर, LCH प्रचंड (लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर), Tejas Fighter Jet (पूर्ण स्वदेशी विमान), पिनाका राकेट सिस्टम (Multi Barrel Rocket launcher), वरुणास्त्र (Anti Submarine Missile) आदि की उपलब्धता के कारण भारतीय सेना विश्व की श्रेष्ठतम सेनाओं में गिनी जाती है। ऑपरेशन सिन्दूर में निर्धारित लक्ष्य पर मार और शत्रु के ड्रोन एवं मिसाइल को मार गिराने में हम सक्षम हुए हैं।

11 वर्ष के सफलतम कालखंड में केवल विदेशों से शस्त्र खरीद ही नहीं हमने स्वयं के आत्मनिर्भर होने के मंत्र को भी पहचाना है। अब हम भारत में उन्नत एवं आधुनिक स्वदेशी शस्त्रों का निर्माण भी कर रहे हैं। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, रुस्तम यूएवी ड्रोंस का डीआरडीओ द्वारा लखनऊ में निर्माण, रूस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, टाटा-डसाल्ट के साथ राफेल के मुख्य भाग का हैदराबाद में हम निर्माण करने वाले हैं। रक्षा उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 174% की वृद्धि हुई है। रक्षा उत्पादन 2014-15 में 46,529 करोड़ रुपए की तुलना में 2023-

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नीति के कारण अब हम खरीदने अर्थात् आयात करने वाले देश नहीं हम बेचने वाले अर्थात् निर्यात करने वाले देश बन गए हैं। 2004 से 2014 अर्थात् 10 वर्षों में हमने 4,312 करोड़ रुपए का निर्यात किया था। 2014 से 2024 में 88,319 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है

24 में 1,27,265 करोड़ रुपए हुआ है।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी-17 नवंबर, 2021 ("Rashtra Raksha Samarpan Parv", झांसी में) के अपने संबोधन में कहा कि—

"भारत अपनी रणनीतिक व सुरक्षा आवश्यकताएं अन्य देशों पर निर्भर होकर पूरा नहीं कर सकता... सरकार निरंतर 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में प्रयासरत है।"

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नीति के कारण अब हम खरीदने अर्थात् आयात करने वाले देश नहीं हम बेचने वाले अर्थात् निर्यात करने वाले देश बन गए हैं। 2004 से 2014 अर्थात् 10 वर्षों में हमने 4,312 करोड़ रुपए का निर्यात किया था। 2014 से 2024 में 88,319 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। 2024 - 25 में केवल एक वर्ष में ही हमने 23,622 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। आयात में 21% की कमी करके 11 वर्षों में निर्यात में 34% की वृद्धि करने में देश सक्षम हुआ है। आज हम लगभग 80 से अधिक देशों में रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे स्वदेशी शस्त्रों की सफलता को देखकर विश्व में हमारे शस्त्रों की मांग भी बढ़ गयी है।

देश को नक्सल मुक्त करने के मोदी सरकार के संकल्प ने देश के सामान्य नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास जगाया है। नक्सली हिंसा में लिप्त आतंकी अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं। 2014 में नक्सल आतंकवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी। 11 वर्षों बाद 2025 में वह संख्या मात्र 6 रह गई है। बड़े-बड़े इनामी नक्सली आतंकी मुठभेड़ में मारे गए हैं। सरकार के नक्सलमुक्त देश के संकल्प से लगता है कि भावी पीढ़ी नक्सलवाद नाम ही भूल जाएगी।

प्रत्येक प्रकार की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 2 सितंबर, 2022 को कोच्चि में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया, जिसमें औपनिवेशिक 'सेंट जॉर्ज क्रॉस' को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित अष्टकोणीय प्रतीक को स्थान दिया गया। इसमें अशोक स्तंभ, लंगर और नौसेना का आदर्श वाक्य 'शं नो वरुणः' अंकित है, जो भारत की समुद्री विरासत और आत्मगौरव का प्रतीक है। नए भारत का संकल्प— घर में घुसकर आतंकियों को मारेंगे, केवल कहना मात्र नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक एवं ऑपरेशन सिंदूर में हमने यह करके दिखाया है। 'खून एवं पानी एक साथ नहीं बहेगा', सिंधु नदी समझौता रद्द कर हमने आतंक के प्रति अपने दृष्टिकोण को विश्व के सामने स्पष्ट किया है। पूर्व सैनिकों के कल्याण, अग्निवीर योजना, विजयदशमी पर राफेल जैसे शस्त्रों का पूजन एवं दीपावली त्योहार में सैनिकों के मध्य प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, सीमावर्ती सैनिक चौकियों पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जी का प्रवास - यह सभी उपक्रम हमारे सुरक्षित भारत के संकल्प को प्रकट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति, पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने, आतंकवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण को विश्व के सम्मुख रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल देश की एकजुटता को प्रकट करने का कूटनीतिक सराहनीय प्रयास है।

भारत को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यह प्रयास देश की जनता में यह विश्वास जगाने में सफल हुए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) हैं)

अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती समारोह

लोकमाता अहिल्याबाई भारत की विरासत की एक महान संरक्षिका थीं: नरेन्द्र मोदी

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 मई को भोपाल, मध्य प्रदेश में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने 'मां भारती' को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की नारी शक्ति का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म जयंती है। यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए प्रेरणा का अवसर है और राष्ट्र निर्माण के महान प्रयासों में योगदान देने का क्षण है। देवी अहिल्याबाई को उद्धृत करते हुए उन्होंने दोहराया कि सच्चे शासन का मतलब लोगों की सेवा करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है।

देवी अहिल्याबाई: दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर का नाम सुनकर गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके असाधारण व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देवी अहिल्याबाई दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं, जो दर्शाती हैं कि चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों, परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इतिहास का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने इस कहा कि ढाई सौ से तीन सौ साल पहले, जब देश उत्पीड़न की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, ऐसे असाधारण कार्य करना - इतने बड़े कि पीढ़ियां आज भी उनको याद करती हैं - कोई आसान काम नहीं था।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने कभी भी ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा के बीच अंतर नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा अपने साथ शिवलिंग रखती थीं। यह उनकी गहरी भक्ति को दर्शाता है। उस समय की चुनौतियों पर विचार करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे युग में राज्य का नेतृत्व करना कांटों का ताज पहनने के समान था। फिर भी, लोकमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को एक नई दिशा प्रदान की, स्वयं को सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया।

श्री मोदी ने कहा, "लोकमाता अहिल्याबाई भारत की विरासत की एक महान संरक्षिका थीं।" प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि ऐसे समय में जब देश की संस्कृति, मंदिर और तीर्थ स्थलों पर हमला हो रहा था, उन्होंने उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित देश भर में कई मंदिरों के जीर्णोद्धार में उनके योगदान का उल्लेख किया।

श्री मोदी ने रेखांकित किया कि माता अहिल्याबाई ने एक अनुकरणीय शासन मॉडल लागू किया, जिसमें गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। उन्होंने कृषि, वन उपज पर आधारित कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने छोटी नहरें बनवाईं और लगभग 250-300 साल पहले कई तालाबों का निर्माण करवाकर जल संरक्षण के प्रयास किए। श्री मोदी ने आदिवासी समुदायों और खानाबदोश समूहों के लिए उनके दूरदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने इन समूहों की आजीविका बढ़ाने के लिए अप्रयुक्त भूमि पर कृषि में सहयोग दिया।

श्री मोदी ने कहा, "देवी अहिल्याबाई होल्कर को हमेशा लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करने और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करने जैसे उनके महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनके समय में चर्चा करना भी मुश्किल था।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक चुनौतियों के बावजूद देवी अहिल्याबाई ने इन प्रगतिशील सुधारों का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने मालवा सेना में एक विशेष महिला यूनिट भी बनाई और गांवों में महिला सुरक्षा समूह स्थापित किए, जिससे सुरक्षा और सशक्तीकरण सुनिश्चित हुआ। ■

माता अहिल्याबाई न केवल धर्म रक्षक थीं, बल्कि संस्कृति रक्षक और समाज सुधारक भी थीं : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 31 मई, 2025 को जयपुर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम से पहले श्री नड्डा ने जयपुर में प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लिया। श्री नड्डा ने माता अहिल्याबाई होलकर के बहुआयामी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर ने धर्म, संस्कृति और समाज सुधार तीनों क्षेत्रों में असाधारण कार्य किया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को भी उसी परंपरा का आधुनिक रूप बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, जनधन, स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं से महिलाओं को नई ताकत दी है। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी श्री राधा मोहन दास अग्रवाल, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, उप-मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी एवं श्री प्रेमचंद बैरवा जी, केंद्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती अलका गुर्जर, सांसद श्री सी. पी. जोशी सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि मुझे पुण्यश्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के इस पावन अवसर पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अक्सर शताब्दियां मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं, लेकिन उस स्मृति की सच्ची गरिमा तभी होती है जब हम उनके कार्यों और जीवन से प्रेरणा लेकर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। केवल चर्चा कर लेना पर्याप्त नहीं होता। हम इस चर्चा से कुछ सीखकर इसे अपने जीवन में उतारें। हम सभी जानते हैं कि माता अहिल्याबाई न केवल धर्म रक्षक थीं, बल्कि संस्कृति की रक्षक और समाज सुधारक भी थीं। बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं जिनमें ये सभी गुण एक साथ समाहित होते हैं।

> अहिल्याबाई का नेतृत्व अठारहवीं शताब्दी में न केवल अद्वितीय था, बल्कि उनका प्रभाव भी अत्यंत निर्णायक रहा। वे संकल्पशक्ति की प्रतिमूर्ति थीं, जो संकल्प कर लिया, उसे पूर्ण करना उनके जीवन का ध्येय बन जाता था

वह इक्कीसवीं शताब्दी नहीं, बल्कि अट्ठारहवीं शताब्दी थी। वह समय जब मुगलों का शासन था और महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ऐसे समय में अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति का उदय होना और उनके द्वारा समाज को दिशा देना, हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।

उन्होंने कहा कि आज प्रोग्रेसिव बात करना एक फैशन हो सकता है, लेकिन अठारहवीं शताब्दी में नई दृष्टि देना और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना, यह बहुत बड़ा प्रेरणा का विषय है। इसलिए अहिल्याबाई का नेतृत्व अठारहवीं शताब्दी में न केवल अद्वितीय था, बल्कि उनका प्रभाव भी अत्यंत निर्णायक रहा। वे संकल्पशक्ति की प्रतिमूर्ति थीं, जो संकल्प कर लिया, उसे पूर्ण करना उनके जीवन का ध्येय बन जाता था। साथ ही, वे साहस से परिपूर्ण थीं और विचारधारा के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध थीं। उनका जीवन एक लक्ष्य के लिए समर्पित था। माता अहिल्याबाई में राजनीति के सारे गुण-दोषों की गहरी समझ थी। वे कूटनीति की ज्ञाता थीं और साथ ही एक साहसी तथा निर्भीक महिला भी। इसीलिए आज हम सभी को माता अहिल्याबाई होलकर से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज हम 'गुड गवर्नेंस' की बात करते हैं, लेकिन सोचिए अठारहवीं शताब्दी में, जब उनके पति कुंभेर की लड़ाई में शहीद हो गए, तब उन्होंने शासन संभाला और सुशासन की मिसाल कायम की। आज जब हम सुशासन की बात करते हैं, तो याद रखना चाहिए कि उन्होंने उस दौर में, जब संसाधनों की कमी थी, अहमदनगर में उत्तम प्रशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। माता अहिल्याबाई होलकर की सभी योजनाएं लोकहितकारी थीं, जो दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली सिद्ध हुईं। माता अहिल्याबाई ने संस्कृति और धार्मिक धरोहर के संरक्षण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जब संस्कृति और धार्मिक धरोहर की बात होती है तो चाहे वह काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर हो या बिहार का कोई अन्य प्राचीन मंदिर उनके पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने तन-मन-धन से कार्य किया। साथ ही, हर मंदिर के साथ धर्मशालाएं बनवाना भी उन्होंने सुनिश्चित किया। इस प्रकार अहिल्याबाई ने संस्कृति की रक्षा के साथ-साथ धर्म को भी प्रोत्साहित किया। ■

प्रदेश, जिला एवं मंडल स्तर के पदाधिकारियों की बैठक, मदुरै (तमिलनाडु)

तमिलनाडु में पारदर्शी एवं राष्ट्रवादी सरकार की जरूरत है : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 8 जून, 2025 को मदुरै में भाजपा तमिलनाडु के राज्य, जिला एवं मंडल स्तर के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। श्री शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और भाजपा की चुनावी उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि अब तमिलनाडु में पारदर्शी एवं राष्ट्रवादी सरकार की ज़रूरत है। श्री शाह ने डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए कहा कि तमिलनाडु बदलाव के दौर में है और 2026 में एनडीए सरकार बनेगी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष श्री नैनार नागेंद्रन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री के. अन्नामलाई, केन्द्रीय मंत्री श्री एल. मुरुगन, भाजपा तमिलनाडु सह-प्रभारी श्री सुधाकर रेड्डी सहित अन्य नेतागण मंच पर उपस्थित रहे।

श्री शाह ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब तमिल नागरिकों के लिए 450 करोड़ रु. की लागत से पोषण किट भेजे। लेकिन इस नेक कार्य को भी घोटाले में बदल दिया गया। एक निजी कंपनी को ठेका देकर भारी घपले किए गए और गरीबों के पेट पर लात मारी गई। तमिलनाडु की जनता सब देख रही है और अब समय आ गया है कि डीएमके को हटाकर एक पारदर्शी, ईमानदार और राष्ट्रभक्त सरकार को चुना जाए। तमिलनाडु में 46,000 करोड़ रु. से अधिक के रेत खनन में बड़े घोटाले हुए। आज गरीब आदमी को अपना घर बनाने के लिए महंगी रेत खरीदनी पड़ती है, जिसका पैसा सीधे डीएमके पार्टी की तिजोरी में जाता है। इस घोटाले के लगभग 40,000 करोड़ रुपये से तमिलनाडु के हर गांव के प्राइमरी स्कूलों में दो नए कमरे बनाए जा सकते थे, लेकिन डीएमके सरकार ने इस पैसा का चूना लगा दिया। मेरे पास उनके घोटालों की लंबी सूची है। यह तमिलनाडु की सरकार 100% विफल रही है।

श्री शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आज तमिलनाडु के हर शहर और गांव से मंडल कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। जब आप अपने गांव, शहर या टाउन जाएंगे, मेरा आपसे एक ही आग्रह है जब तक तमिलनाडु में डीएमके सरकार को नहीं हटाते, तब तक आराम नहीं करेंगे। यह टीम इसी संकल्प के साथ काम करेगी। वर्ष 2026 में भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके साथ मिलकर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेगी, एनडीए के साथियों के साथ मिलकर लड़ेगी। तमिलनाडु की जनता इस बार डीएमके को हटाएगी। ■

विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

'भयमुक्त पश्चिम बंगाल केवल भाजपा सरकार ही बना सकती है'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में घुसपैठ, राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने की जमकर आलोचना की। श्री शाह ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ने व विजयी होने के लिए मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि राज्य को पुनः सोनार बांग्ला और भयमुक्त पश्चिम बंगाल केवल भाजपा की सरकार ही बना सकती है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष श्री सुकांत मजूमदार, बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे, सहप्रभारी श्री अमित मालवीय एवं अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

श्री शाह ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने 'सोनार बांग्ला' के सपने को भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार और हिन्दुओं पर अन्याय के जरिये पूरी तरह तहस-नहस कर दिया है। टीएमसी शासन में SSC भर्ती घोटाला, पशु तस्करी घोटाला, डियर लॉटरी घोटाला, कोयला घोटाला, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला, राशन घोटाला, मिड डे मील घोटाला, नगर पालिका भर्ती घोटाला, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन और गाय तस्करी से जुड़े घोटाले हुए, जिससे हज़ारों करोड़ रुपये की लूट हुई और यह सारा पैसा पश्चिम बंगाल की गरीब जनता का है।

श्री शाह ने कहा कि ममता बनर्जी से बताएं कि 10 साल तक केन्द्र में सत्ता में रहकर, 15 साल मुख्यमंत्री रहकर, यूपीए और इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए उन्होंने बंगाल को क्या दिया? सोनिया-मनमोहन सरकार ने 10 साल में बंगाल को 2.09 लाख करोड़ रु. दिए, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 वर्षों में 8.27 लाख करोड़ रु. की योजनाएं दीं। लेकिन मोदी जी द्वारा भेज गया पैसा टीमसी के सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया। जब तक बंगाल में कमल के फूल की सरकार नहीं बनती प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 50 लाख करोड़ भी भेज दें, फिर भी यह पैसा जनता तक नहीं पहुंचेगा। श्री शाह ने कार्यकर्ताओं और जनता से आह्वान किया कि देश की सुरक्षा, घुसपैठ रोकने, भ्रष्टाचार मिटाने, माताओं-बहनों को सुरक्षा देने और हिन्दुओं को निर्भय करने के लिए इस बार भाजपा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को मौका दीजिए। भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज से 2026 के चुनाव तक दिन-रात मेहनत करें। ■

दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज–चिनाब पुल और भारत के पहले केबल–स्टेड रेल पुल अंजी ब्रिज का उद्घाटन

दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज 'चिनाब ब्रिज' भारत की महत्वाकांक्षा का प्रमाण है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छह जून को जम्मू-कश्मीर के कटरा में 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। वीर जोरावर सिंह की भूमि को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम भारत की एकता और दृढ़ संकल्प का भव्य उत्सव है। श्री मोदी ने कहा कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से कश्मीर घाटी अब भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लाइन परियोजना केवल एक नाम नहीं है, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर की नई ताकत और भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक है।

"कई लोगों ने इस रेल सेवा का सपना देखा था। जो काम अंग्रेज नहीं कर सके, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरा किया और कश्मीर घाटी अब देश के बाकी हिस्सों से जुड़ गई है।"

उमर अब्दुल्ला, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री

क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के अनुरूप श्री मोदी ने चिनाब और अंजी रेल पुलों का उद्घाटन किया और जम्मू-कश्मीर के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने जम्मू में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला।

उल्लेखनीय है कि नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह 1,315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है जिसे भूकंप और तेज हवा की स्थिति में दृढता के साथ अडिग रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पुल पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के ज़रिए कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा करने में सिर्फ़ 3 घंटे लगेंगे और यात्रा समय में 2-3 घंटे की कमी आएगी। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल-स्टेड रेल ब्रिज है जो इस चुनौतीपूर्ण भूभाग में राष्ट्र की सेवा करेगा।

चिनाब ब्रिज की ऊंचाई पेरिस के एफिल टॉवर से भी अधिक

श्री मोदी ने भारत के इंजीनियरों और श्रमिकों की इंजीनियरिंग प्रतिभा और अटूट समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज भारत की महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जहां लोग एफिल टॉवर देखने के लिए पेरिस जाते हैं, वहीं चिनाब ब्रिज की ऊंचाई उससे भी अधिक है, जिससे यह न केवल एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्धि बन गया है, बल्कि एक उभरता हुआ पर्यटक आकर्षण भी बन गया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री ने अंजी ब्रिज को इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया, जो भारत का पहला केबल-समर्थित रेलवे ब्रिज है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ये संरचनाएं केवल स्टील और कंक्रीट से बनी नहीं हैं, बल्कि भारत की शक्ति के जीवंत प्रतीक हैं, जो पीर पंजाल पहाड़ों के ऊबड़-खाबड़ ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धियां एक 'विकसित राष्ट्र' के लिए भारत के विजन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो साबित करती हैं कि भारत की प्रगति का सपना जितना बड़ा है, उतना ही उसका लचीलापन, क्षमता और दृढ़ संकल्प भी है।

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा, "जम्मू और कश्मीर भारत माता का मुकुट है, जो उज्ज्वल रत्नों से सुसज्जित है - प्रत्येक रत्न इस क्षेत्र की असीम शक्ति और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है।" उन्होंने इसकी प्राचीन संस्कृति, परंपराओं, आध्यात्मिक चेतना, मनमोहक परिदृश्यों, औषधीय जड़ी-बूटियों, फलते-फूलते बागों और जीवंत युवा प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये गुण भारत के मुकुट में बहुमूल्य रत्नों की तरह चमकते हैं। ■

एकात्म मानव दर्शन केवल एक 'मॉडल' नहीं बल्कि एक जीवंत दृष्टि है

पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा एकात्म मानववाद पर प्रस्तुत व्याख्यान शृंखला की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय (31 मई और 1 जून) राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान के तत्वावधान में लोक नीति शोध केन्द्र, एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस संगोष्ठी में प्रख्यात विद्वानों, नीति निर्माताओं और विचारकों ने दीनदयालजी के दर्शन की प्रासंगिकता पर विचार-विमर्श किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने समापन भाषण दिया। श्री नड्डा ने बताया कि किस तरह एकात्म मानववाद विचारधारा से शासन की ओर बढ़ा है, उन्होंने कल्याण और आर्थिक सुधारों को दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन की अभिव्यक्ति बताया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री अरुण कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में एकात्म मानववाद के आधारभूत सिद्धांतों पर जोर दिया, जिसे उन्होंने भारत की सभ्यतागत चेतना से उभरने वाला विश्व दृष्टिकोण बताया।

भाजपा राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) श्री शिवप्रकाश ने दीनदयालजी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ के विकास के बारे में बताया। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का जीवंत चित्रण किया, जो कठिनाई के बावजूद राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहा। उन्होंने अपने वक्तव्य में दीनदयालजी की विनम्रता, बुद्धिमत्ता और संगठनात्मक प्रतिभा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके जीवन का अभिन्न अंग विचार, वचन और कर्म की एकरूपता थी, जो उनके गहन आध्यात्मिक अनुशासन और राष्ट्रवादी विचार का प्रतिबिंब था।

डॉ. महेश चंद्र शर्मा ने एकात्म मानववाद की विद्वत्तापूर्ण व्याख्या की, जिसमें उन्होंने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि सिद्धांत एकरूपता नहीं, बल्कि एकता और संतुलन चाहता है। उन्होंने कहा कि दीनदयालजी का दृष्टिकोण विकेंद्रीकृत शासन, आत्मनिर्भर गांवों और आर्थिक नैतिकता को प्रोत्साहित करता है, जो धर्म पर आधारित विकास का एक विशिष्ट भारतीय मॉडल प्रस्तुत करता है।

अर्थव्यवस्था और कल्याण पर एक सत्र में भारतीय शिक्षण मंडल के श्री शंकरानंद ने एकात्म मानववाद को विकेन्द्रीकृत, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विचार से जोड़ा।

संगोष्ठी के पहले दिन के दूसरे सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एकात्म मानववाद की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसके मूल सिद्धांतों को पीएम मुद्रा योजना और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी मौजूदा नीतिगत पहलों से जोड़ा। पंडित जी के अंत्योदय के विचार - अंतिम व्यक्ति का उत्थान - का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक विकास को नैतिकता, आध्यात्मिक चेतना और विकेंद्रीकृत उद्यम द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धन सृजन को धर्म और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ा जाना चाहिए, न कि भौतिक अधिकता के साथ।

तीसरे सत्र में डॉ. एम.एस. चैत्रा और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने राष्ट्रीय कायाकल्प में शिक्षा और संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया। संगोष्ठी के पहले दिन के समानांतर सत्र में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गनाइजर के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर ने संगोष्ठी में एकात्म मानववाद के पर्यावरणीय आयाम पर विचार रखे।

कार्यक्रम के दूसरे दिन पहले सत्र में श्री नितिन गोखले और भाजपा नेता श्री के. अन्नामलाई ने सांस्कृतिक एकता और सभ्यतागत विमर्शों के माध्यम से भारत के सुरक्षा प्रतिमान को फिर से परिभाषित किया।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ. गजानन डांगे ने दूसरे दिन के दूसरे सत्र को संबोधित किया, ग्रामीण विकास के प्रमुख विशेषज्ञ डॉ. डांगे ने 'मिट्टी से आत्मा तक' विषय पर एक मुख्य भाषण दिया - एकात्म दर्शन ने स्वावलंबन और परस्पर

सहयोग जैसे सिद्धांतों के माध्यम से सभ्यतागत मूल्यों का विकास किया।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए सतत विकास पर जोर दिया।

संगोष्ठी के दूसरे दिन के समानांतर सत्र में श्रीमती ममता यादव एवं भाजयुमो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अभिनव प्रकाश ने आंतरिक अनुशासन, सभ्यतागत विमर्श और चरित्र निर्माण के माध्यम से महिलाओं और युवाओं की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला।

श्री जे. नंदकुमार, श्री एस. गुरुमूर्ति और डॉ. गुरु प्रकाश पासवान सहित अन्य प्रख्यात वक्ताओं ने धर्म, आध्यात्मिक एकता और सांस्कृतिक स्मृति पर आधारित भारत का सभ्यतागत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

'नेतृत्व की विरासतः राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय' विषय पर एक सत्र को श्री जे. नंदकुमार और डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने संबोधित किया। श्री एस. गुरुमूर्ति ने अपने संबोधन में एकात्म मानववाद को एक राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक जीवंत सभ्यतागत नैतिकता के रूप में प्रस्तुत किया।

अपने समापन भाषण में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि किस तरह एकात्म मानववाद विचारधारा से शासन की ओर बढ़ा है, उन्होंने कल्याण और आर्थिक सुधारों को दीनदयाल उपाध्याय के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने राष्ट्रीय नीति के लिए एकात्म मानववाद को मार्गदर्शक बनाने का आग्रह किया। श्री नड्डा ने श्रोताओं को याद दिलाया कि भारतीय विचार कोई स्थिर या अमूर्त चीज नहीं है। यह गतिशील है। यह शाश्वत सिद्धांतों में निहित रहते हुए समय के साथ विकसित होता है।

यही कारण है कि एकात्म मानव दर्शन केवल एक 'मॉडल' नहीं है, बल्कि एक जीवंत दृष्टि है - दीनदयाल जी द्वारा लगाया गया एक पौधा जिसे अब एक वटवृक्ष के रूप में विकसित होना चाहिए, जो न केवल भारत को, बल्कि दुनिया को आश्रय और दिशा प्रदान करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक स्थायी तंत्र उभरना चाहिए जो समकालीन चुनौतियों के जवाब में एकात्म मानववाद का विकास करे। ■

'डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जीः एक शिक्षाविद् की राजनीतिक यात्रा' पुस्तक का विमोचन

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के जीवन और विरासत पर आधारित पुस्तक 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जीः एक शिक्षक की राजनीतिक यात्रा' का विमोचन 1 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान (एसपीएमआरएफ) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में किया गया, जिसमें प्रमुख राजनीतिक और शैक्षणिक व्यक्तित्व उपस्थित रहे।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष प्रो. पी. कनागासबपति ने संयुक्त रूप से पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कमल संदेश के एसोसिएट एडिटर श्री विकास आनंद हैं और इसे वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है।

यह पुस्तक डॉ. मुकर्जी के अद्वितीय जीवन पर प्रकाश डालती है, जो एक प्रख्यात शिक्षाविद् और राजनेता थे और जिन्होंने भारत के राष्ट्रवादी विमर्श को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुस्तक देश की राजनीतिक यात्रा में डॉ. मुकर्जी के योगदान को प्रस्तुत करती है, जो उनकी प्रारंभिक शैक्षणिक उपलब्धियों से लेकर भारतीय जनसंघ की स्थापना तक है, जिसने आज की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वैचारिक नींव रखी- पर प्रकाश डालती है।

यह पुस्तक न केवल डॉ. मुकर्जी की शैक्षणिक प्रतिभा और

कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति के रूप में उनके कार्यकाल पर प्रकाश डालती है, बल्कि अपने समय की तुष्टीकरण की राजनीति के प्रति उनके दृढ़ विरोध, नेहरू-लियाकत समझौते को लेकर नेहरू मंत्रिमंडल से उनके सैद्धांतिक इस्तीफे और जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में पूर्ण एकीकरण की मांग में उनकी ऐतिहासिक भूमिका पर भी प्रकाश डालती है।

कश्मीर में वर्ष 1953 में हिरासत के दौरान डॉ. मुकर्जी की रहस्यमयी मृत्यु भारत के इतिहास में सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाओं में से एक है। यह पुस्तक इन घटनाओं को अकादमिक दृष्टिकोण के साथ संबोधित करती है और सार्वजनिक समझ को समृद्ध करने के लिए विभिन्न पहलुओं को छूती है। ■

आयुष्मान भारत योजना का कवरेज बहुत प्रभावशाली है: विंस्टन पीटर्स

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 30 मई, 2025 को नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के उप-प्रधानमंत्री श्री विंस्टन पीटर्स से भेंट की।

इस बातचीत के दौरान श्री नड्डा ने भाजपा के संगठनात्मक ढांचे और विविध समुदायों तक इसके व्यापक पहुंच प्रयासों के प्रमुख पहलुओं को साझा किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के बीच प्रतिनिधिमंडल आदान-प्रदान कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा, ताकि दोनों पार्टी के बीच घनिष्ठ अंतर-पार्टी संबंध विकसित किए जा सकें।

इस दौरान मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख स्वास्थ्य पहलों पर भी चर्चा की गई, जिसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया। श्री विंस्टन पीटर्स आयुष्मान भारत योजना के कवरेज से बहुत प्रभावित हुए।

दोनों नेताओं ने पिछले दशक में भारत-न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर बात की तथा विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में गहन सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया।

उन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली को विस्तृत और प्रभावशाली बताया। श्री विंस्टन पीटर्स न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री भी हैं और रेलवे मंत्री और रेसिंग मंत्री के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी संभालते हैं। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

चिनाब (जम्मू एवं कश्मीर) में 06 जून, 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन एवं ब्रिज डेक का दौरा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जम्मू एवं कश्मीर में 06 जून, 2025 को यूएसबीआरएल परियोजना की टीम एवं कर्मचारियों से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

बिहार में 29 मई, 2025 को पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कानपुर (उत्तर प्रदेश) में 30 मई, 2025 को विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भोपाल (मध्य प्रदेश) में 31 मई, 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल) में 29 मई, 2025 को सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 20 जून, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2025-27
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

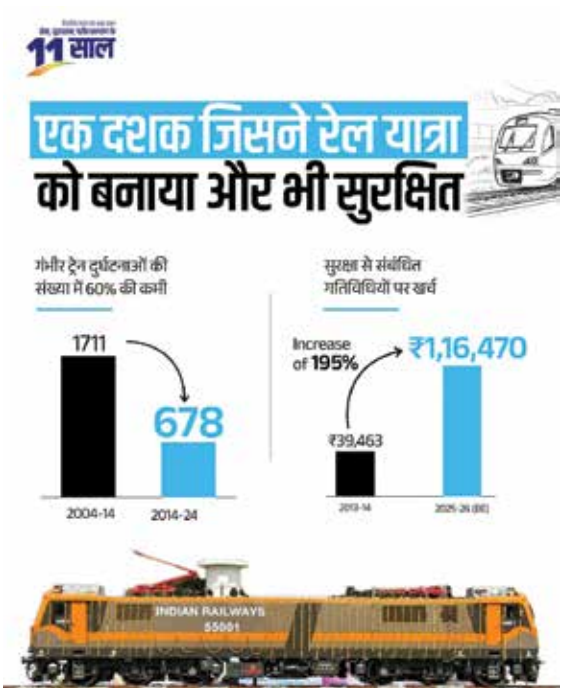

छायाकार: अजय कुमार सिंह